[Shri A. S. Alva]

Clause 3 (1) of the Bill reads thus:

"If the President, on receipt of a report or otherwise, is of opinion that there are good grounds for making an investigation into the misbehaviour or incapacity of a Judge, he may constitute a Special Tribunal for the purpose of making such an investigation and forward the grounds of such investigation to the Special Tribunal.".

Under this clause, the power has been given only to the President. If the President does not refer the case to a tribunal, then no action can be taken against the particular judge. The question is whether that is consistent with the provision in the Constitution. My submission to you is that it is not consistent. As a matter of fact, it will be open to any Member to bring forward a motion to say that a judge should be removed from his office, and then the matter could be investigated under clause (5) of article 124, which reads:

"Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of a Judge under clause (4).".

Even the verdict of the tribunal is not final. What is final is the satisfaction of the Houses of Parliament that a judge has committed misbehaviour or is incapable of doing his functions. So, my submission is that ultimately Parliament has the authority, and as such clause 3 which is incorporated in the Bill will clearly be a violation of the constitutional provision.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Member may continue his speech tomorrow.

Now, we shall take up the half-an-hour discussion.

---

**16.00 hrs.**

## RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES

**श्री हुकम चन्द कछवाय** (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 512, दिनांक 9 सितम्बर, 1965 के बारे में दिये गये जवाब से उत्पन्न हुई है ।

आज देश के अन्दर जो मूल्य-वृद्धि हो रही है उस के तीन कारण हैं । (क) चीजों का स्वाभाविक अभाव, (ख) मुनाफाखोरी, और (ग) घाटे की अर्थ व्यवस्था ।

मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया कि उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाये । दरअसल मूल्य वृद्धि का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाना चाहिए और वह वैज्ञानिक विश्लेषण इस आधार पर किया जाय कि वस्तुओं के अभाव से कितनी मूल्य वृद्धि हुई, घाटे की अर्थ व्यवस्था के कारण कितनी मूल्य वृद्धि हुई और मुनाफाखोरी के कारण कितनी मूल्य वृद्धि हुई ? हमारी सरकार अगर इस ओर विचार करती तो निश्चय ही इस सम्बन्ध में कोई हल निकल सकता था ।

मूल्य वृद्धि मुनाफाखोरी के कारण हुई उस का पूरा बोझ व्यापारियों पर पड़ना चाहिए उपभोक्ताओं पर नहीं । उपभोक्ताओं पर केवल उतना ही बोझ पड़ना चाहिये जितना कि चीजों के स्वाभाविक अभाव के कारण मूल्य वृद्धि हुई है । सरकार द्वारा इस प्रकार का विश्लेषण नहीं किया गया जो बड़ी भारी भूल हुई है । सरकार इस सम्बन्ध में पहले से अगर विचार करती तो हो सकता

---

*Half-An-Hour Discussion.

था कि इस प्रकार का दिन हमें न देखना पड़ता । इस प्रकार का विश्लेणथ पश्चिमी देशों ने किया । यहां भी हो सकता है और होना चाहिए ।

विश्लेषण के पश्चात् यह सिद्धांत अपनाना चाहिए . . . .

**श्री शिव नारायण** : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस म इस समय कोरम नहीं है।

**Mr. Deputy-Speaker:** I am sorry there is no quorum. The House stands adjourned till 10 A.M. tomorrow.

**16.07 hrs.**

*The Lok Sabha then adjourned till ten of the Clock on Wednesday, September 22, 1065/Bhadra 31, 1887 (Saka).*

---

GMGIPND—LS II—1423(Ai)LSD -12-10.65—1020.